सबसे बड़ा बैंकिंग फ्रॉड: दो बधावन भाइयों ने बैंकों को लगाया 34615 करोड़ रुपये का चूना

जेपी सिंह

आर्थिक उदारीकरण का सर्वाधिक फायदा बैंकों से फर्जीगिरी करके अरबों खरबों के फ्रॉड करने वालों को हुआ है। सीबीआई ने अब तक के सबसे बड़े बैंकिंग फ्रॉड का पर्दाफाश किया है। बैंकिंग फ्रॉड के मामले में डीएचएफएल के प्रवर्तकों कपिल वधावन और धीरज वधावन के खिलाफ नया केस रजिस्टर किया है। इस मामले में बैंकों के एक समूह को 34,615 करोड़ रुपये का चूना लगाया गया है। बैंकों के इस समूह की अगुवाई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कर रहा था। सीबीआई को इस मामले में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी जनरल मैनेजर विपिन कुमार शुक्ला ने लिखित शिकायत दी थी। इसके पहले सबसे बड़े घोटाले के तौर पर 22 हजार करोड़ का बैंक घोटाला सामने आया था।

डीएचएफएल का यह मामला सीबीआई के पास रजिस्टर्ड अब तक का सबसे बड़ा बैंकिंग फ्रॉड है। 34 हजार करोड़ रुपयों से भी ज्यादा के इस घोटाले में सीबीआई ने इस मामले में घोटाला करने वाली कंपनी दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और उसके सहयोगियों पर विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत मुकदमा दर्जकर आज देश भर में एक दर्जन से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान अनेक आपत्तिजनक और महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद किए गए हैं। देर शाम तक छापेमारी का दौर जारी था।

सीबीआई को इस मामले में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी जनरल मैनेजर विपिन कुमार शुक्ला ने लिखित शिकायत दी थी इसके पहले सबसे बड़े घोटाले के तौर पर 22 हजार करोड़ का बैंक घोटाला सामने आया था। इस शिकायत में कहा गया था कि दीवान हाउसिंग फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड और उसकी सहयोगी कंपनियों और सहयोगियों ने 17 बैंकों के समूह का नेतृत्व कर रहे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को 34 हजार 615 करोड़ रुपए का चूना लगाया है इसके पहले सबसे बड़े घोटाले के तौर पर 22 हजार करोड़ का बैंक घोटाला सामने आया था। यह चूना साल 2010 से साल 2019 के बीच लगाया गया इसके पहले सबसे बड़े घोटाले के तौर पर 22 हजार करोड़ का बैंक घोटाला सामने आया था।

सीबीआई को दी गई शिकायत में कहा गया था कि डीएचएफएल कंपनी काफी पुराने समय से बैंकों से क्रेडिट सुविधाएं लेती रही है। यह कंपनी अनेक क्षेत्रों में काम करती है. इस कंपनी ने 17 बैंकों के समूह से जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बैंक ऑफ महाराट्र आईडीबीआई यूको बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक पंजाब एंड सिंध बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे बैंकों से दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, कोचीन आदि जगहों पर क्रेडिट सुविधा ली। इसके पहले सबसे बड़े घोटाले के तौर पर 22 हजार करोड़ का बैंक घोटाला सामने आया था।

आरोप है कि इस कंपनी ने बैंकों से कुल 42 हजार करोड़ से ज्यादा का लोन लिया, लेकिन उसमें से 34615 हजार करोड़ रुपए का लोन वापस नहीं किया साथ ही उनका एक खाता 31 जुलाई 2020 को एनपीए हो गया इसके पहले सबसे बड़े घोटाले के तौर पर 22 हजार करोड़ का बैंक घोटाला सामने आया था।

आरोप है कि इस कंपनी ने बैंक से जिस काम का पैसा लिया था उस काम में नहीं लगाया जो फंड बैंकों से लिया जाता था इसके पहले सबसे बड़े घोटाले के तौर पर 22 हजार करोड़ का बैंक घोटाला सामने आया था। वह एक महीने के थोड़े समय के भीतर ही दूसरी कंपनियों में भेज दिया जाता था।

जांच के दौरान यह भी पाया गया कि लोन का पैसा सुधाकर शेट्टी नाम की एक शख्स की कंपनियों में भी भेजा गया साथ ही यह पैसा दूसरी कंपनियों के ज्वाइंट वेंचर में लगाया गया। यह भी पता चला है कि लोन का पैसा 65 से ज्यादा कंपनियों में भेजा गया। इसके लिए बाकायदा अकाउंट बुक में फर्जीवाड़ा किया गया।

सीबीआई ने इस मामले में दीवान हाउसिंग फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड उसके निदेशक कपिल वधावन धीरज वधावन एक अन्य व्यक्ति सुधाकर शेट्टी अन्य कंपनियों गुलमर्ग रिलेटेर्स, स्काईलार्क बिल्डकॉन दर्शन डेवलपर्स, टाउनशिप डेवलपर्स समेत कुल 13 लोगों के खिलाफ विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया।

एफआईआर में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। बैंक ने आरंभिक बयान में कहा है कि उनका कोई कर्मचारी इस घोटाले में फिलहाल शामिल नहीं पाया गया है। लेकिन सीबीआई को शक है कि इतना बड़ा घोटाला बिना बैंक कर्मियों की मिलीभगत के नहीं हो सकता। लिहाजा उनकी भूमिका की जांच भी की जा रही है। सीबीआई ने इस मामले में आज मुंबई समेत अनेक शहरों की एक दर्जन से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की। देर शाम तक चली छापेमारी के दौरान अनेक आपत्तिजनक और महत्वपूर्ण दस्तावेज तथा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद किए गए हैं। देर शाम तक छापों का दौर जारी था। इस मामले में कुछ राजनेताओं की भूमिका की जांच भी की जा सकती है । मामले की जांच जारी है ।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने उसकी अगुवाई वाले बैंकों के समूह को 40,623.36 करोड़ रुपये का चूना लगाने के लिए डीएचएफएल के पुराने प्रबंधन और प्रवर्तकों के खिलाफ सीबीआई से जांच करने की मांग की थी। 40,623.36 करोड़ रुपये का आंकड़ा 30 जुलाई 2020 के आधार पर था। बैंक ने अपनी शिकायत में ऑडिट फर्म केपीएमजी की जांच के नतीजों का भी जिक्र किया था। केपीएमजी ने पाया था कि उक्त मामले में नियमों व प्रावधानों को ताक पर रखा गया, अकाउंट के साथ छेड़छाड़ की गई, गलत आंकड़े सामने रखे गए ।

अधिकारियों ने कहा कि एजेंसी ने बैंक से 11 फरवरी 2022 को मिली शिकायत के आधार पर कार्रवाई की। डीएचएफएल के प्रवर्तक कपिल वधावन और धीरज वधावन पहले से ही तलोजा जेल में हैं। दोनों को यस बैंक के साथ फ्रॉड के मामले में सीबीआई और ईडी के केस के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। दोनों के ऊपर आरोप है कि उन्होंने यस बैंक के को-फाउंडर राणा कपूर के साथ मिलकर यस बैंक के साथ फ्रॉड किया ।

डीएचएफएल का यह मामला सीबीआई के पास रजिस्टर्ड अब तक का सबसे बड़ा बैंकिंग फ्रॉड है। सीबीआई ने हाल ही में पता लगाया कि फ्रॉड में एबीजी शिपयार्ड को 22,842 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। अधिकारियों ने कहा कि एजेंसी ने बैंक से 11 फरवरी, 2022 को मिली शिकायत के आधार पर कार्रवाई की।

क्या आनंद महिंद्रा ने पूर्व सैनिकों को दिया था जॉब का ऑफर? सेना के पूर्व दिग्गजों ने पूछे हैं तीखे सवाल

जनचौक ब्यूरो

सेना भर्ती की नई योजना अग्निपथ को लेकर सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक विवाद जारी है। भारत के बड़े कारोबारी आनंद महिंद्रा ने ट्वीट करके इस योजना का समर्थन किया है। इसके बाद अब पूर्व सैनिकों और उद्यमियों के बीच इस भर्ती योजना पर वाद-विवाद शुरू हो गया है। पूर्व नौसेना प्रमुख और 1971 की जंग के हीरो एडमिरल अरुण प्रकाश ने आनंद महिंद्रा के ट्वीट पर जवाब देते हुए लिखा, इस स्कीम का इंतज़ार क्यों? क्या महिंद्रा ग्रुप ने अब तक उन हज़ारों कुशल-अनुशासित पूर्व सैनिकों से संपर्क किया है, जो हर साल रिटायर हो रहे हैं और जिन्हें दूसरा करियर बनाने के लिए मौक़े की तलाश है? आपके ग्रुप से ऐसे आंकड़े मिलना अच्छा होगा।

वहीं महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा, आरपीजी एंटरप्राइज़ चेयरमैन हर्ष गोयनका और बायोकॉन लिमिटेड चेयरपर्सन किरन मजूमदार शॉ अग्निपथ भर्ती योजना के समर्थन में उतरे हैं।

आनंद महिंद्रा ने सोमवार को ट्वीट किया था, "अग्निपथ योजना को लेकर हो रही हिंसा से दुखी हूँ। पिछले साल जब इस योजना पर विचार किया जा रहा था, तब मैंने कहा था और आज दोहराता हूँ कि अग्निवीर को जो अनुशासन और कौशल मिलेगा वह उन्हें उल्लेखनीय रूप से रोज़गार योग्य बनाएगा। महिंद्रा ग्रुप इस तरह के प्रशिक्षित, सक्षम युवाओं को हमारे यहाँ नौकरी का मौक़ा देगी।" आनंद महिंद्रा के ट्वीट पर जवाब देते हुए हर्ष गोयनका ने लिखा, "आरपीजी ग्रुप भी नौकरी के लिए अग्निवीरों का स्वागत करेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि दूसरी कॉर्पोरेट कंपनियां भी इस प्रतिज्ञा में हमारे साथ आएं और हमारे युवाओं को भविष्य के लिए आश्वासन दे।"

हर्ष गोयनका के इस ट्वीट को कोट करते हुए किरन मजूमदार शॉ लिखती हैं, "मुझे पक्का भरोसा है कि इंडस्ट्रियल जॉब मार्केट में नौकरी पाने की प्रक्रिया में अग्निवीरों को ख़ास फ़ायदा मिलेगा।"

पूर्व सैनिक ही उठा रहे सवाल

लेकिन उद्योगपतियों के इन प्रस्तावों पर पूर्व सैन्य प्रमुख सवाल उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि हर साल हज़ारों की संख्या में सैनिक रिटायर होते हैं, उनमें से कितनों को इन्होंने नौकरियां दी हैं। एडमिरल अरुण प्रकाश ने आनंद महिंद्रा से पूछा है कि अग्निवीरों का इंतज़ार क्यों करना है, अब भी हज़ारों की संख्या में कुशल और ट्रेंड पूर्व सैनिक मिल जाएंगे।

अग्निपथ विरोधी प्रदर्शन

पूर्व एयर वाइस मार्शल मनमोहन बहादुर ने आनंद महिंद्रा को टैग करते हुए लिखा, "आनंद महिंद्रा सर, क्या हमें वो आंकड़े मिल सकते हैं जो पूर्व नौसेना प्रमुख ने मांगे हैं? मैं इसी तरह के वादों को सुनते हुए 40 साल बाद सेवा से रिटायर हुआ हूँ।"

ट्विटर यूज़र अभिषेक कुमार ने आनंद महिंद्रा के ट्वीट पर सवाल किया, "मैं नेवी का इंजीनियरिंग सेलर रहा हूँ और 31 जुलाई 2017 को सेवा मुक्त हुआ। मैंने एक अच्छी नौकरी के लिए महिंद्रा ग्रुप से संपर्क किया लेकिन उन्होंने मेरे आवेदन पर कोई जवाब नहीं दिया। पाँच साल बाद मैं आज भी बेरोज़गार हूँ और अब अचानक कंपनियां अग्निवीरों को नौकरी देने के लिए तैयार हैं। क्या मज़ाक है..."

कर्नल सलीम दुर्रानी लिखते हैं, "प्रिय महिंद्रा जी, हर साल करीब 60 से 70 हज़ार पूरी तरह प्रशिक्षित जवान रिटायर होते हैं। अगर पूछने की इजाज़त हो तो, इनमें से कितने आपके पास नौकरी कर रहे हैं? हम अग्निवीरों पर बाद में आएंगे, जब समय आएगा।"

पूर्व कर्नल अशोक कुमार सिंह ने महिंद्रा को टैग करते हुए लिखा, "महिंद्रा जी कृपया अमेरिकी कॉरपोरेट से कुछ सीखिए। कैसे वो अपने पूर्व सैनिकों को मदद करते हैं और मनोबल बढ़ाते हैं। आप सिर्फ़ बातें कर रहे हैं क्योंकि आपको मोदी ने यही करने को कहा है।"

अंग्रेज़ी अख़बार द टेलिग्राफ़ की एक ख़बर के अनुसार डायरेक्टोरेट जनरल रिसेटलमेंट (डीजीआर) के पास 30 जून 2021 तक के मौजूद ताज़ा आंकड़ों से पता लगता है कि सरकारी नौकरियों में पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित सीटों और असल में होने वाली भर्तियों में काफ़ी बड़ा अंतर है।

केंद्र सरकार के विभागों में ग्रुप सी की नौकरियों में 10 फ़ीसदी और ग्रुप डी की नौकरियों में 20 फ़ीसदी पद पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित हैं। हालाँकि, ग्रुप सी की कुल नौकरियों में इनकी संख्या केवल 1.29 फ़ीसदी और ग्रुप डी में 2.66 फ़ीसदी है।

अग्निपथ योजना पर भारी विरोध के बाद बीते सप्ताह गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय ने इस स्कीम के तहत सेना में चार साल सेवा देने वालों को 10 फ़ीसदी अतिरिक्त आरक्षण देने का एलान किया था।

30 जून 2021 तक के आंकड़ों के अनुसार देश में पूर्व सैनिकों की संख्या 26 लाख 39 हज़ार 20 थी। इनमें से 22 लाख 93 हज़ार 378 थल सेना, 2 लाख 7 हज़ार 534 वायु सेना और 1 लाख 38 हज़ार 108 नौसेना से सेवानिवृत्त हुए हैं।